

Group on Housing in October, 1977.
The Working Group submitted an Interim Report to serve as an approach paper for the Five Year Plan 1978—83. In order to finalize the Interim Report, the Working Group was reconstituted in May, 1978. Government would take a decision on the report of the reconstituted Working Group after it submits its report.

माही, कदन और लिलवानी बांधों के निर्माण से डूबने वाले गांव

4715. श्री हीरा भाई : क्या कृषि और सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माही बांध और कदन बांध के निर्माण कार्य लगभग पूरे होने वाले हैं और लिलवानी बांध के निर्माण की भी योजना है ; यदि हाँ, तो उपरोक्त तीन बांधों के निर्माण से बंसवाड़ा जिले में कितने गांव और कितने एकड़ भूमि जलमग्न होगी ; और

(ख) क्या जिन किसानों की भूमि जलमग्न हो गई है या जिनको भूमि जलमग्न होने की सम्भावना है ; उन्हें भूमि के आवंटन के बारे में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है और न ही विस्थापित किसानों के लिए किसी वैकल्पिक रोजगार का प्रबंध किया गया है और यदि हाँ, तो इसके बाद कारण हैं और यदि नहीं, तो कितने किसानों को भूमि का आवंटन किया जा चुका है और शेष किसानों को भूमि कब तक आवंटित कर दी जायेगी और यह भूमि कहाँ पर आवंटित की जायेगी ?

कृषि और सिचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा आवासीय मकानों का निर्माण

4716. श्री यादवेन्द्र दत्त :

श्री श्यामलाल धूर्वे :

श्री भारत सिंह चौहान :

क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने दिल्ली में आवासीय मकान बनाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी योजना का ब्लॉक क्या है और कितने मकान बनाने का विचार है और इस काम में अनुमानतः कितनी राशि खर्च होगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बखत) : (क) कन्द्रीय लोक निर्माण विभाग दिल्ली में कन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सामान्य पूल वास का निर्माण करता रहा है और भविष्य में भी ऐसे वास का निर्माण करता रहेगा।

(ख) वर्ष 1978-79 के दौरान, सरकार ने दिल्ली में सामान्य पूल वास में 43.54 करोड़ रुपये की लागत से 15,300 मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी है। 6.71 करोड़ रुपये की लागत से 800 दोहरे कमरे वाले होस्टल वास के निर्माण की भी स्वीकृति दी है। प्रारम्भ में, इस होस्टल को संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन सम्मेलन के लिए प्रयोग में लाया जाएगा और उस के बाद यह कन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को आवंटन के लिए सामान्य पूल वास में शामिल कर दिया जाएगा।

पत्राचार पाठ्यक्रम के लिये नये विश्वविद्यालय की स्थापना

4717. श्री हरगोविंद वर्मा : क्वा शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी विश्वविद्यालयों द्वारा चलाये जा रहे पत्राचार पाठ्यक्रमों को एक साथ मिला कर एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो किस समय तक और उस स्थान का नाम क्या है जहाँ उसका मुख्यालय स्थापित होगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।